

करेंट अफेयर्स माध्य प्रदेश (संग्रह)



जून
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश.....	3
उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन.....	3
पीएम गतिशक्ति योजना के तहत रेलवे अवसंरचना परियोजनाएँ.....	5
राजा भभूत सिंह.....	6
पन्ना टाइगर रिजर्व में केन-बेतवा परियोजना पर चिंता.....	8
अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025.....	10
जल गंगा संवर्द्धन अभियान.....	12
मंत्रिमंडल ने 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी.....	13
पगारा बाँध के पास चीता देखे गए.....	15
ICAR-NIHSAD “कैटेगरी A रिडरपेस्ट फैसिलिटी “ के रूप में नामित.....	17
मध्य प्रदेश में ब्लैकबक का अवैध शिकार.....	18
तानसेन का मकबरा.....	21

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



SCAN ME

UPSC
क्लासरूम
कोर्सस



SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



SCAN ME

दृष्टि लर्निंग
ऐप



SCAN ME

मध्य प्रदेश

उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के नवनिर्मित सतना हवाई अड्डे तथा उन्नत दतिया हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जो क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने और उड़ान योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

❖ सतना हवाई अड्डा:

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा 36.96 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सतना हवाई अड्डा पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा।
- यह हवाई अड्डा चित्रकूट और मैहर जैसे प्रमुख स्थलों से संपर्क को सुदृढ़ करेगा, जिससे सांस्कृतिक तथा औद्योगिक संबंधों को मजबूती मिलेगी।
- प्रमुख विशेषताओं में पुनः कालीनयुक्त रनवे, डोर्नियर-228 विमानों के लिये पार्किंग स्थल, एक ATC टावर और एक फायर स्टेशन शामिल हैं।
- ❑ सतत विकास की दृष्टि से इसमें 100% LED प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटें और बागवानी के लिये उपचारित जल पुनः उपयोग प्रणाली शामिल हैं।

❖ दतिया हवाई अड्डा:

- उन्नत दतिया हवाई अड्डे का विकास 60.63 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जो इस ऐतिहासिक शहर को राष्ट्रीय विमानन ग्रिड से जोड़ेगा।
- ❑ पीतांबरा पीठ और दतिया पैलेस जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के लिये प्रसिद्ध दतिया में इस परियोजना से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- वर्तमान में यह हवाई अड्डा ATR-72 विमान के संचालन हेतु उपयुक्त है तथा भविष्य में Airbus A-320 विमानों के संचालन के लिये तैयार किया जा रहा है।
- अवसंरचना में पुनर्परिष्कृत रनवे, एप्रन बे (apron bays), ATC टावर, फायरफाइटिंग सेवाएँ, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं।

❖ सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण को गति देने की दिशा में:

- दोनों हवाई अड्डों के संचालन से बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र होंगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच में सुधार होगा।
- ये परियोजनाएँ उड़ान योजना के अंतर्गत समावेशी विकास पर केंद्र सरकार के विशेष फोकस को दर्शाती हैं, जिससे वंचित क्षेत्रों के लिये किफायती हवाई यात्रा संभव हो रही है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उड़ान योजना

परिचय:

- उड़ान का उद्देश्य देश के दूरवर्ती क्षेत्रों तक वायु कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए विमानन का अधिक से अधिक विस्तार करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- यह योजना **राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (NCAP) 2016** के तहत तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य बाजार संचालित तथा वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से **टियर-2 और टियर-3 शहरों** को जोड़ना था।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** इसके कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।

विशेषताएँ:

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)** : उचित किराया सुनिश्चित करने के लिये एयरलाइनों को वित्तीय सहायता।
 - योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **क्षेत्रीय संपर्क निधि (RCF)** का प्रावधान किया गया है।
 - वहनीयता सुनिश्चित करने के लिये **हवाई किराये की सीमा** निर्धारित की गई है।
 - क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन को व्यवहार्य बनाने के लिये विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर करों में कमी** के साथ एयरलाइनों को अन्य रियायतें दी गई हैं।
 - केंद्र, राज्य, **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** और निजी हवाईअड्डा संचालकों के बीच **सहयोगात्मक शासन** पर ध्यान दिया गया है।

उड़ान के अंतर्गत प्रमुख नवाचार:

- उड़ान यात्री कैफे:** कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर किफायती यात्री कैफे शुरू किये गए हैं, जो उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- सीप्लेन परिचालन:** देश भर में **50 से अधिक चिह्नित जल निकायों** से निविदा आमंत्रित करने के लिये उड़ान चक्र 5.5 शुरू किया गया है।
- कृषि उड़ान योजना:** किसानों को समर्थन देने और कृषि उपज के लिये मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिये डिजाइन की गई **कृषि उड़ान**, विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों से समय पर और लागत प्रभावी हवाई रसद की सुविधा प्रदान करती है।
- कोविड-19 महामारी** के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा सामान पहुँचाने के लिये **लाइफलाइन उड़ान** शुरू की गई थी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India- AAI) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय** के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1995 में **राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण** को मिलाकर किया गया था।
- यह भारतीय हवाई क्षेत्र और आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में **हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएँ** भी प्रदान करता है।
- AAI के कार्यों में हवाई अड्डे का विकास, हवाई क्षेत्र नियंत्रण, यात्री और कार्गो टर्मिनल प्रबंधन तथा संचार एवं नेविगेशन सहायता का प्रावधान शामिल हैं।
- AAI 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील हवाई क्षेत्र में **हवाई नेविगेशन सेवाएँ** प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पीतांबरा पीठ

- ❖ पीतांबरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर परिसर है, जिसमें एक आश्रम भी सम्मिलित है।
- ❖ यहाँ स्थित श्री वनखंडेश्वर शिवलिंग को महाभारत काल का माना जाता है। यह मंदिर शक्ति साधना के प्रमुख केंद्रों में एक है।
- ❖ पीठ की स्थापना वर्ष 1935 में स्वामीजी महाराज द्वारा दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की गई थी।

पीएम गतिशक्ति योजना के तहत रेलवे अवसंरचना परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो प्रमुख रेलवे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी संयुक्त अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है।

मुख्य बिंदु

- ❖ रेलवे परियोजनाओं के बारे में:
 - ❶ इन परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 176 किमी. होगी, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों में फैली होंगी।
 - ❷ इनका कार्य वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पूरा होना निर्धारित है।
 - ❸ इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यात्रियों और माल के आवागमन को सुचारू बनाना तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
 - ❹ ये परियोजनाएँ “न्यू इंडिया” की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जो क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करके और रोजगार बढ़ाकर स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर नाने का लक्ष्य रखती हैं।
- ❖ गाँवों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
 - ❶ विस्तारित रेलवे क्षमता से 784 गाँवों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे लगभग 19.74 लाख लोगों की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी।
 - ❷ ये गलियारे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उपज और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी प्रमुख वस्तुओं के परिवहन के लिये महत्वपूर्ण हैं।
 - ❸ इस पहल से कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित होंगे जिससे ग्रामीण आजीविका में योगदान मिलेगा।
- ❖ माल ढुलाई क्षमता और आर्थिक लाभ:
 - ❶ इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष 18.40 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई का भार संभालने का अनुमान है।
 - ❷ उन्नत माल ढुलाई से आपूर्ति शृंखला को अनुकूलित करने, रसद लागत को कम करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
- ❖ पर्यावरणीय प्रभाव:
 - ❶ नई रेल लाइनों से तेल आयात में 20 करोड़ लीटर की कमी आने की उम्मीद है।
 - ❷ इससे CO₂ उत्सर्जन में भी 99 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
 - ❸ यह टिकाऊ बुनियादी ढाँचे और कम कार्बन अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

परिचय:

- अक्तूबर 2021 में शुरू किया गया PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रुपये की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में भारत के बुनियादी ढाँचे में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
- इसे **BISAG-N** (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है।
 - इसे गतिशील **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म** पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट कार्य योजनाओं के आँकड़ों को एक व्यापक डाटा बेस में शामिल किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करना, समयसीमा को कम करना तथा अंतरमंत्रालयी बाधाओं को दूर करके भारत की वैश्विक स्पर्द्धा को बढ़ाना है।
- PM गतिशक्ति का विज्ञान एक विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा विकसित करना है, जो जीवन को आसान बनाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाए।

प्रमुख विशेषताएँ:

- डिजिटल एकीकरण:** इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे 16 मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में निर्बाध बुनियादी अवसंरचना परियोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- बहु-क्षेत्रीय सहयोग:** इसमें **सागरमाला परियोजना**, **भारतमाला परियोजना**, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क बंदरगाह और **उड़ान** सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों से बुनियादी अवसंरचनात्मक पहलों को शामिल किया गया है।
- आर्थिक क्षेत्र:** आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये **टेक्सटाइल क्लस्टर**, फार्मास्युटिकल हब, **रक्षा गलियारे** और कृषि क्षेत्र जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग:** **BiSAG-N** द्वारा विकसित उन्नत स्थानिक नियोजन उपकरण और **इसरो सैटेलाइट मानचित्रण**, नियोजन और प्रबंधन के लिये डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)

- इसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं और यह सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है।
- यह एक एकीकृत आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करने के लिये आर्थिक प्रवृत्ति की निरंतर समीक्षा करती है तथा विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियों एवं गतिविधियों की देखरेख करती है, जिसके लिये उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

राजा भभूत सिंह

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ने 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह को सम्मान देने के लिये **पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य** का नाम उनके नाम पर रख दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

❖ राजा भभूत सिंह के बारे में:

- ❶ 1857 के विद्रोह में योगदान: राजा भभूत सिंह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध **1857 के विद्रोह** के दौरान एक प्रमुख किंतु कम प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे।
- ❷ गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ: उन्होंने **सतपुड़ा** के जंगलों और भू-भाग का गहन ज्ञान रखते हुए प्रभावी गुरिल्ला हमले किये तथा वर्षों तक ब्रिटिश सेनाओं का प्रतिरोध किया।
- ❸ तात्या टोपे के सहयोगी: उन्होंने **तात्या टोपे** जैसे राष्ट्रीय नेताओं से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया।
- ❹ शहादत और विरासत: अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिये **मद्रास इन्फैंट्री** को तैनात किया और अंततः वर्ष 1860 में उनकी हत्या कर दी। उनकी विरासत आज भी **कोरकू लोक परंपराओं** में जीवित है।

❖ मध्य प्रदेश में सम्मानित अन्य जनजातीय नेता:

- ❶ टंट्या भील: वर्ष 2021 में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या भील के नाम पर रखा गया।
- ❷ भीमा नायक: भील स्वतंत्रता सेनानी **भीमा नायक** के सम्मान में एक स्मारक की घोषणा की गई है।
❶ भीमा नायक स्मारक: नायक ने 1818-1850 के बीच खानदेश में भील प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
- ❸ रानी कमलापति: भोपाल स्थित **हबीबगंज रेलवे स्टेशन** का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। वह गिन्नौर किले (वर्तमान सीहोर) के शासक निज़ाम शाह की सातवीं पत्नी थीं।
- ❹ शंकर शाह और रघुनाथ शाह: वर्ष 2021 में यह घोषणा की गई कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम गोंड राजघरानों के नाम पर रखा जाएगा।

❖ पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य:

❖ परिचय:

- ❶ यह दक्कन प्रायद्वीप जैवभौगोलिक क्षेत्र में स्थित है तथा मध्य भारत के जैविक प्रांत के अंतर्गत आता है।
- ❷ यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जो भारत में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है।
- ❸ इस रिजर्व का सबसे ऊँचा स्थान धूपगढ़ है, जो समुद्र तल से 1,352 मीटर ऊँचा है।

❖ रिजर्व के भीतर संरक्षित क्षेत्र:

- ❶ इस **बायोस्फीयर रिजर्व** में तीन प्रमुख संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं: **बोरी वन्यजीव अभयारण्य**, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभयारण्य।
- ❷ ये तीनों क्षेत्र मिलकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का निर्माण करते हैं, जो मध्य भारत के लिये एक महत्वपूर्ण संरक्षण परिदृश्य है।

कोरकू जनजाति

परिचय:

- ❶ कोरकू समुदाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र में निवास करता है।
- ❷ परंपरागत रूप से, कोरकू स्थायी कृषक तथा कुशल किसान रहे हैं। वे अपने क्षेत्रों में आलू और कॉफी जैसी फसलें उगाने में अग्रणी थे।
- ❸ हालाँकि आज अधिकांश कोरकू समुदाय के पास पर्याप्त कृषि भूमि है, लेकिन कुछ लोगों ने 19वीं सदी के अंत तक झूम खेती से हटकर वानिकी तथा खेतीहर मजदूरी की ओर रुख किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ कोरकू गाँव आमतौर पर घास और लकड़ी से बनी छोटी-छोटी झोपड़ियों से बने होते हैं।
- ❖ वे वंशानुगत, पुरुष-वंश-आधारित समुदायों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व परंपरागत मुखिया करते हैं।
- ❖ सांस्कृतिक प्रथाएँ और विश्वासः
 - कोरकू जनजाति की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है तथा परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ आज भी सक्रिय रूप से उपयोग में हैं।
 - वे अपने पूर्वजों को देवता के रूप में पूजते हैं तथा उनकी स्मृति में 'मुंडा' नामक स्मारक स्तंभ स्थापित करते हैं।

1857 का विद्रोह

ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल (1856-62) के दौरान घटित

विद्रोह का केंद्र	नेता	ब्रिटिश अधिकारी (विद्रोह का दमन)
दिल्ली	बहादुर शाह ज़फर	जॉन निकोलसन
लखनऊ	बेगम हजरत महल	हेनरी लॉरेंस
कानपुर	नाना साहेब	सर कॉलिन कैपबेल
झाँसी और ग्वालियर	रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे	जनरल ह्यूज रोज
बरेली	खान बहादुर खाँ	सर कॉलिन कैपबेल
बिहार	कुंवर सिंह	विलियम टेलर
इलाहाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली	कर्नल ओनसेल

विद्रोह की विफलता:

- सीमित विद्रोह - रियासतों तथा दक्षिणी प्रांतों ने इसमें भाग नहीं लिया
- प्रभावी नेतृत्व का न होना
- सीमित संसाधन - लोग/सिपाही/सैनिक, धन और शस्त्र
- अंग्रेजी- शिक्षित मध्यम वर्गी, संपन्न महाजनों, व्यापारियों और बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में मदद की

परिणाम:

- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ
- भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन
- वायसरॉय ने गवर्नर जनरल का स्थान लिया
- व्यवस्था के सिद्धांत को समाप्त - दलित पुत्रों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई
- ब्रिटिश अधिकारियों में भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि हुई

विद्रोह के कारण:

- राजनीतिक - ब्रिटिश विस्तार नीति (व्यपगत का सिद्धांत)
- सेना - भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले व्यवहार मुख्यतः उनके साथ जो किसान पृष्ठभूमि वाले थे,
- आर्थिक - किसानों पर अत्यधिक कर का आरोपण, राजस्व संग्रह के सख्त तरीके, ब्रिटिश वस्तुओं के आने से स्थानीय उद्योगों को क्षति
- सामाजिक-धार्मिक - पश्चिमी सभ्यता का तेजी से प्रसार, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करना, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने संबंधी मान्यता
- तात्कालिक कारण - चंडी एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाकर धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करने की अफवाहें

1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें

- वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वातंत्र्य सगर
- पुरन चंद जोशी द्वारा लिखित रिबेलियन, 1857: ए सिम्पोजियम
- जॉर्ज थॉमस मैलेसन द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, 1857-1858
- क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा लिखित द ग्रेट म्यूटिनी
- इकबाल हुसैन द्वारा लिखित रिबेलियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेलिय ऑफ 1857
- खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा लिखित एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ: अनसंग हरीरोज़ ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडियेंस



पन्ना टाइगर रिज़र्व में केन-बेतवा परियोजना पर चिंता

चर्चा में क्यों ?

वन्यजीव विशेषज्ञों और वन अधिकारियों ने चिंता जताई है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत निर्माण कार्य से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व (PTR) में वन्यजीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

❖ पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में:

- पन्ना भारत का 22वाँ और मध्य प्रदेश का 5वाँ बाघ अभयारण्य है।
- यह **विंध्य पर्वतमाला** में स्थित है तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी तथा इसे वर्ष 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1975 में बनाए गए पूर्व गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल है।
 - इस अभयारण्य के जंगल कभी पन्ना, छतरपुर और बिजावर की पूर्व रियासतों के शाही परिवारों के लिये शिकारगाह हुआ करते थे।

❖ वनस्पति:

- शुष्क पर्णपाती वनों** तथा **घास के मैदानों** का प्रभुत्व।
- उत्तर में यह अभयारण्य सागौन के जंगलों से घिरा हुआ है।
- पूर्व में इसकी सीमा सागौन-करधई मिश्रित वनों से लगती है।

❖ जीव-जंतु:

- यह रिजर्व **बाघों**, **भालुओं**, **तेंदुओं** और धारीदार लकड़बग्घों की महत्वपूर्ण आबादी का घर है।
- अन्य उल्लेखनीय माँसाहारी प्रजातियों में सियार, भेड़िये, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियाँ और धब्बेदार जंगली बिल्ली शामिल हैं।
- उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक फैली विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ वन्य जीवों की पूर्वी और पश्चिमी आबादी को जोड़ने में मदद करती हैं।

❖ केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का अवलोकन और उद्देश्य:

- प्रधानमंत्री** ने दिसंबर 2024 में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक पहुँचाना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 मिलियन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है।

❖ निर्माण एवं वन प्रभाव:

- मार्च 2025 में, प्राधिकारियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य चंद्र नगर रेंज में दौधन बाँध स्थल तक सड़क का निर्माण शुरू किया।
- 15 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्ष काट दिये गए, जिससे प्रभावित क्षेत्र से वन्यजीवों का पलायन शुरू हो गया।

❖ वन्यजीव अशांति और प्रवासन:

- शाकाहारी जानवर उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पारंपरिक प्रादेशिक क्षेत्र बाधित हो रहे हैं।
- परियोजना स्थल पर बढ़ती मानवीय उपस्थिति और मशीनरी के कारण बंदर तथा पक्षी इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने पन्ना टाइगर रिजर्व में वन क्षरण और शिकार की कमी को लेकर चिंता जताई है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट से पता चला है कि शिकार घनत्व घटकर 6 जानवर/वर्ग किमी रह गया है, जो आदर्श स्थिति 30-60 से बहुत कम है।

❖ सरकारी उपाय:

- विस्थापित वन्यजीवों को नए अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, जैसे:
 - रानीपुर टाइगर रिजर्व** (उत्तर प्रदेश)

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

- ❏ रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
- ❏ डॉ. भीम राव वन्यजीव अभयारण्य (म.प्र.)
- ❖ अन्य वनों से शिकार प्रजातियों को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना पर काम चल रहा है।
- ❖ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये सरकार ने प्रतिपूरक वनरोपण और वन्यजीव पुनर्वास उपायों की योजना बनाई है।
- ❏ रिजर्व का 60 वर्ग किमी तक विस्तार प्रस्तावित है तथा छतरपुर और पन्ना जिलों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पहले ही चल रहा है।
- ❖ पर्यावरण मंत्रालय ने तीन शर्तों के साथ परियोजना को मंजूरी दी:
 - ❏ पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमाओं का विस्तार करना।
 - ❏ प्रतिपूरक वनरोपण के रूप में 2.5 मिलियन पेड़ लगाए जाएंगे।
 - ❏ रेडियो कॉलर के माध्यम से बाघ और तेंदुए के व्यवहार की निगरानी करना।
- ❖ अब तक वन विभाग ने वनरोपण के लिये निर्धारित भूमि का केवल 30% ही अधिगृहीत किया है।

अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों ?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने, मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए “अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि सम्मेलन 2025” का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ PMMSY के अंतर्गत प्रमुख मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन:
 - ❏ केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत प्रमुख मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ने हलाली बाँध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया और विभिन्न PMMSY-समर्थित पहलों की आधारशिला रखी, जिनका उद्देश्य जलीय कृषि ढाँचे को मजबूत करना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना तथा अंतर्देशीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करना है।
- ❖ लाभार्थियों को सहायता और तकनीकी एकीकरण:
 - ❏ मंत्री ने मत्स्य सहकारी समितियों, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPOs) और मत्स्य स्टार्टअप्स सहित अनेक लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।
 - ❏ मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और जलीय कृषि बीमा प्रदान किया गया, जिससे हाशिये पर स्थित समुदायों को एकीकृत डिजिटल पहुँच तथा केंद्रित बीमा कवरेज प्राप्त हुआ।
- ❖ 2015 से अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि:
 - ❏ वर्ष 2015 से सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत 38,572 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
 - ❏ इसके परिणामस्वरूप भारत का कुल मछली उत्पादन 104% बढ़कर, 2013-14 में 95.79 लाख टन से 2024-25 में 195 लाख टन हो गया।
 - ❏ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि ने इस उत्पादन में 75% से अधिक योगदान दिया, जो 2024-25 में 140% बढ़कर 147.37 लाख टन तक पहुँच गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह क्षेत्र वर्ष भर उत्पादन, कुशल संसाधन उपयोग को संभव बनाता है तथा कम उपयोग वाली भूमि को आय-उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तित करता है, जिससे ग्रामीणों और छोटे किसानों की आजीविका को समर्थन मिलता है।
- ❖ प्रौद्योगिकी-संचालित विकास और नवाचार:
 - PMMSY और **नीली क्रांति** के तहत सरकार ने 45,000 अंतर्देशीय इकाइयों को स्वीकृति दी, जिससे उत्पादकता में 20 गुना तक वृद्धि हुई।
 - मछली परिवहन, निगरानी तथा सतत् मत्स्य प्रबंधन के लिये ड्रोन के उपयोग की संभावनाएँ तलाशने हेतु **ICAR-CIFRI (केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान)** के साथ एक पायलट परियोजना शुरू की गई।
- ❖ भारत के मत्स्य क्षेत्र की स्थिति:
 - भारत, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है।
 - भारत मछली निर्यात में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो विश्व मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
 - अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा प्रदान करता है। शीर्ष मछली उत्पादक राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

- ❖ मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम PMMSY का उद्देश्य नीली क्रांति के लिये भारत के मत्स्य उद्योग को सतत् और जिम्मेदार तरीके से विकसित करना है।
 - यह मछुआरों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ❖ PMMSY को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ❖ उद्देश्य: PMMSY मत्स्य पालन, उत्पादकता, गुणवत्ता और **बुनियादी ढाँचे** में अंतराल को कम कर मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की गारंटी देते हुए मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण करता है।

नीली क्रांति

- ❖ नीली क्रांति का तात्पर्य अंतर्देशीय, समुद्री मत्स्य पालन और जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य क्षेत्र के एकीकृत तथा सतत् विकास से है।
- ❖ सरकार ने सभी चालू मत्स्यपालन योजनाओं को एक एकीकृत कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया, जिसे “नीली क्रांति: मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन” नाम दिया गया।
- ❖ यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जो संपूर्ण क्षेत्र में लक्षित सहायता सुनिश्चित करती है।

उद्देश्य:

- ❖ मछली उत्पादन को टिकाऊ और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देना।
- ❖ नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना।
- ❖ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ❖ रोजगार के अवसर सृजित करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना।
- ❖ समावेशी विकास को बढ़ावा देना तथा मछुआरों और मत्स्यपालकों को सशक्त् बनाना।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



जल गंगा संवर्द्धन अभियान

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च 2025 को शुरू किये गए मध्य प्रदेश सरकार के जल गंगा संवर्द्धन अभियान से खंडवा ज़िले में नर्मदा की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ का सफल पुनरुद्धार हुआ है।

मुख्य बिंदु

- ❖ जल गंगा संवर्द्धन अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ:
- ❖ 'रिज टू वैली' दृष्टिकोण का उपयोग करके जल संचयन:
 - ⦿ प्रशासन द्वारा 33 किमी लंबे क्षेत्र में जल संरक्षण संरचनाएँ बनाने के लिये 'रिज टू वैली' मॉडल को अपनाया गया।
 - ⦿ इस पद्धति का उद्देश्य पर्वतीय शिखरों (रिज) पर जल की प्रत्येक बूँद को संजोना तथा भूमि पर प्रवाहित जल की मात्रा और गति को धीमा करना है।
 - ⦿ इसका परिणाम यह हुआ कि घोड़ा पछाड़ नदी पुनः बहने लगी है, जिससे इस क्षेत्र की नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह होने की उम्मीद है।
- ❖ नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयास:
 - ⦿ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नर्मदा, चंबल, शिप्रा, बेतवा, सोन, टोंस, ताप्ती, माही, सिंध और बेनगंगा सहित प्रमुख नदियों का सर्वेक्षण किया।
 - ⦿ इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि प्रतिदिन लगभग 450 मिलियन लीटर घरेलू अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जो एक गंभीर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न कर रहा है।
 - ⦿ इस समस्या के समाधान हेतु नगर विकास विभाग द्वारा 869 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कुल उपचार क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की स्थापना की जा रही है।
 - ⦿ यह पहल राज्य की नदियों की जल गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी तथा स्वच्छ व सतत जल संसाधनों को बढ़ावा देगी।
- ❖ आर्द्रभूमि संरक्षण और रामसर मान्यता:
 - ⦿ मध्य प्रदेश ने वर्ष 2002 में केवल एक रामसर स्थल से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक यह संख्या पाँच कर दी है।
 - ⦿ इनमें सांख्य सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, तवा जलाशय तथा भोज वेटलैंड शामिल हैं।
 - ⦿ इंदौर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनकर शहरी जल प्रबंधन में एक मानक स्थापित कर चुका है।
 - ❏ इसके अतिरिक्त, इंदौर में 330 से अधिक पारंपरिक कुओं और बावड़ियों का संरक्षण किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक जल संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान मिला है।
- ❖ नर्मदा नदी:
 - ⦿ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर पश्चिम की ओर बहती है तथा लगभग 98,796 वर्ग किमी. के बेसिन क्षेत्र को कवर करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह नदी लगभग 1,300 किमी. तक फैली हुई है और इसे 41 सहायक नदियाँ जल उपलब्ध कराती हैं।
- यह नदी छत्तीसगढ़ सीमा के पास पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वतमाला से निकलती है।
- एक प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता ने नर्मदा को नामदे नाम से संदर्भित किया है, जो अरब सागर और गंगा बेसिन को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाता है।
- इसमें अनेक झरने हैं, जिनमें जबलपुर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित प्रमुख धुआँधार जलप्रपात भी शामिल है।
- मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा कुंड है, जिसे नदी का पवित्र उद्गम माना जाता है।

❖ जल संसाधन विकास:

- नर्मदा नदी जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।
- इस नदी पर प्रमुख बाँधों में सरदार सरोवर बाँध (गुजरात), इंदिरा सागर बाँध (पुनासा, म.प्र.), ओंकारेश्वर बाँध, बरगी बाँध तथा महेश्वर बाँध शामिल हैं।

❖ नर्मदा बचाओ आंदोलन:

- मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) ने बाँध परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन का विरोध किया।
- उनके योगदान के कारण सर्वोच्च न्यायालय और विश्व बैंक ने इस परियोजना पर अस्थायी रोक लगा दी तथा वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने इस परियोजना से अपने को अलग कर लिया।
- वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित समुदायों के पुनर्वास की शर्त पर चरणबद्ध बाँध निर्माण की अनुमति दी थी।
- निर्माण पूरा होने के बावजूद, NBA जलाशयों के बढ़ते स्तर और विस्थापित आबादी के लिये खतरे पर चिंता जताता रहा है।

मंत्रिमंडल ने 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को मंजूरी दी है, जो नौ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के लिये पहला पदोन्नति अवसर है।

- ❖ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्रमुख पहलों में नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिये पूंजी परियोजनाएँ और नवगठित जिलों में जिला कोषागारों की स्थापना शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

❖ मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025:

- इस कदम का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के लिये उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है और योग्यता आधारित पदोन्नति तथा नई नौकरी रिक्तियों के प्रावधानों के साथ प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करना है।
- ये नियम पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों (ST) और अनुसूचित जातियों (SC) के लिये उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- नये नियमों में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये 20% और अनुसूचित जातियों (SC) के लिये 16% **आरक्षण** की गारंटी दी गई है।
- पदोन्नति योग्यता, वरिष्ठता और उपयुक्तता के संयोजन पर आधारित होगी, जिसमें प्रथम श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये स्पष्ट प्रावधान होंगे।
- लगभग 2 लाख नए पद सृजित किये जाएंगे जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र और कार्यकर्ता:
 - मंत्रिमंडल ने **PM-जनमन योजना** के तहत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी।
 - इस पहल की अनुमानित लागत 143.46 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 72.78 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार 70.68 करोड़ रुपए का योगदान देगी।
- विद्युत पारेषण के लिये पूंजीगत परियोजनाएँ:
 - मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (MPPTCL) की चालू एवं आगामी पूंजीगत परियोजनाओं के लिये वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिये 5,163 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी।
 - प्रमुख आवंटनों में ट्रांसमिशन प्रणालियों के निर्माण और उन्नयन, **सिंहस्थ-2028** के लिये विद्युत अवसंरचना तथा मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिये वित्तपोषण शामिल है।
- नवगठित जिलों में जिला कोषागार:
 - मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों- पांडुर्ना, मैहर और मऊगंज में जिला कोषागारों की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे स्थानीय शासन तथा प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी।

KEY DECISIONS & ALLOCATIONS

➤ The cabinet approved establishment, operation, and construction of 459 new anganwadi centres in special tribal areas under the PM-JANMAN scheme ➤ Approval also given to create 459 honorary posts for anganwadi workers, another 459 posts for anganwadi helpers, and 26 regular supervisory posts ➤ Cabinet also approved a total estimated expenditure	of ₹5,163 crore for ongoing and upcoming capital projects of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited (MPPTCL) for the period 2025-26 to 2029-30 ➤ ₹1,154 crore for construction & upgradation of transmission systems approved by the central transmission unit ➤ ₹185 crore for power infrastructure for Simhastha-2028	➤ ₹54 crore for new EHV (Extra High Voltage) lines for uninterrupted power to Morena Division HQ and northern Gwalior ➤ ₹1,280 crore for capacity enhancement of existing EHV transformers ➤ The cabinet approved the establishment of district treasuries in the newly formed districts of Pandhurna, Maihar, and Mauganj
--	---	---

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पगारा बाँध के पास चीता देखे गए

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में पगारा बाँध के पास कुनो राष्ट्रीय उद्यान से चीते दिखाई दिये, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु

♦ कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना ज़िलों में स्थित, कुनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- इसे अपने पारिस्थितिकी महत्व के कारण वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ।
- इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कुनो नदी के नाम पर रखा गया है, जो चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- यह क्षेत्र मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है और विंध्य पर्वतमाला में स्थित है।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किये गए चीतों का निवास स्थान है।

♦ जीव-जंतु: तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, काला हिरण, सांभर हिरण, घड़ियाल (कुनो नदी)।

♦ वनस्पति: मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ करधई, खैर और सलाई हैं।

♦ प्रोजेक्ट चीता:

- वर्ष 2022 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः स्थापित करना है, इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।
- परियोजना के दूसरे चरण में केन्या से चीते लाकर उन्हें कुनो और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में बसाने की योजना है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- ♦ NTCA एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। NTCA की स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- ♦ NTCA का गठन भारत में बाघ संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने, उक्त अधिनियम के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिये किया गया था।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- ♦ वर्ष 1982 में स्थापित यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- ♦ यह देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सलाह प्रदान करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



चीता (Cheetah)



सामान्य नाम: एशियाई चीता

वैज्ञानिक नाम: एसिनोनक्स जुबेटस (*Acinonyx jubatus*)

- ❖ एसिनोनक्स जुबेटस जुबेटस (एशियाई चीता)
- ❖ एसिनोनक्स जुबेटस वेनाटिकस (अफ्रीकी चीता)

विशेषताएँ:

- ❖ विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- ❖ चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल **200-300** मीटर के लिये तथा **1** मिनट से कम अवधि का होता है।
- ❖ शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता:

- ❖ **अफ्रीकी:** हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा; एशियाई चीते से मोटी
 - ❖ चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता
 - ❖ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं
 - ❖ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** सुषेद्य (**Vulnerable**)
- ❖ **एशियाई:** अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
 - ❖ हल्के पीले रंग की त्वचा: शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल
 - ❖ केवल ईरान में पाए जाते हैं; देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल **12** चीते शेष हैं।
- ❖ **वर्ष 1952:** एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित किया गया
 - ❖ **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** घोर संकटग्रस्त (**Critically Endangered**)



एशियाई चीता



अफ्रीकी चीता

भारत में चीतों का पुनर्वास:

- ❖ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC द्वारा "भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना" जारी की गई थी। (जनवरी 2022)
 - ❖ इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष **2009** में प्रस्तावित की गई थी।
- ❖ सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।
 - ❖ इन आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।
- ❖ नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



ICAR-NIHSAD “कैटेगरी A रिंडरपेस्ट फैसिलिटी” के रूप में नामित

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने ICAR-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल को कैटेगरी A रिंडरपेस्ट होलिंग फैसिलिटी के रूप में नामित किया है।

❖ भारत अब उन छह वैश्विक संस्थानों में शामिल हो गया है, जिन्हें रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री को सुरक्षित रूप से रखने के लिये विश्वसनीय माना गया है।

मुख्य बिंदु

❖ **NIHSAD** (राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान):

- यह भारत की प्रमुख जैव सुरक्षा स्तर-3 (**BSL-3**) सुविधा वाली उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला है, जो विदेशी और उभरते पशु रोगजनकों, रोग निदान तथा उच्च जोखिम वाले जीवों के जैव नियंत्रण पर अनुसंधान करती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हाई सिक्वोरिटी एनिमल डिजीज़ लैबोरेटरी (**HSADL**) के रूप में की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर **NIHSAD** कर दिया गया।
- यह वन हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत एवियन इन्फ्लूएंज़ा, न्यूकैसल रोग और अन्य सीमापार तथा जूनोटिक रोगों के लिये एक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है।
- यह संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**ICAR**), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

❖ **रिंडरपेस्ट:**

- रिंडरपेस्ट, जिसे कैटल प्लेग (मवेशी प्लेग) के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2011 में अपने वैश्विक उन्मूलन तक एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग था।
- उन्मूलन के बावजूद, रिंडरपेस्ट वायरस-युक्त पदार्थ (RVCM) अभी भी विश्व की कुछ प्रयोगशालाओं में मौजूद है, जो जैव सुरक्षा के लिये संभावित खतरा बना हुआ है।
- यह रोग संक्रमित स्त्राव या दूषित भोजन/पानी के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, मुँह में छाले, दस्त और त्वरित मृत्यु शामिल हैं।
- इससे अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में पशुधन की व्यापक हानि हुई, जिससे आर्थिक पतन और खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हुई।
- इस खतरे को नियंत्रित करने के लिये, **FAO** और **WOAH** ने **RVCM** के भंडारण को सख्त वैश्विक निरीक्षण के अंतर्गत उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाओं तक सीमित कर दिया है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)

- ❖ **WOAH**, जिसे वर्ष 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिज़ूटीज़ (**OIE**) के नाम से स्थापित किया गया था, एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
- ❖ इसकी स्थापना वैश्विक रिंडरपेस्ट प्रकोप के प्रत्युत्तर में की गई थी।
- ❖ **WOAH** को विश्व व्यापार संगठन (**WTO**) के स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों (**SPS**) संबंधी समझौते के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स

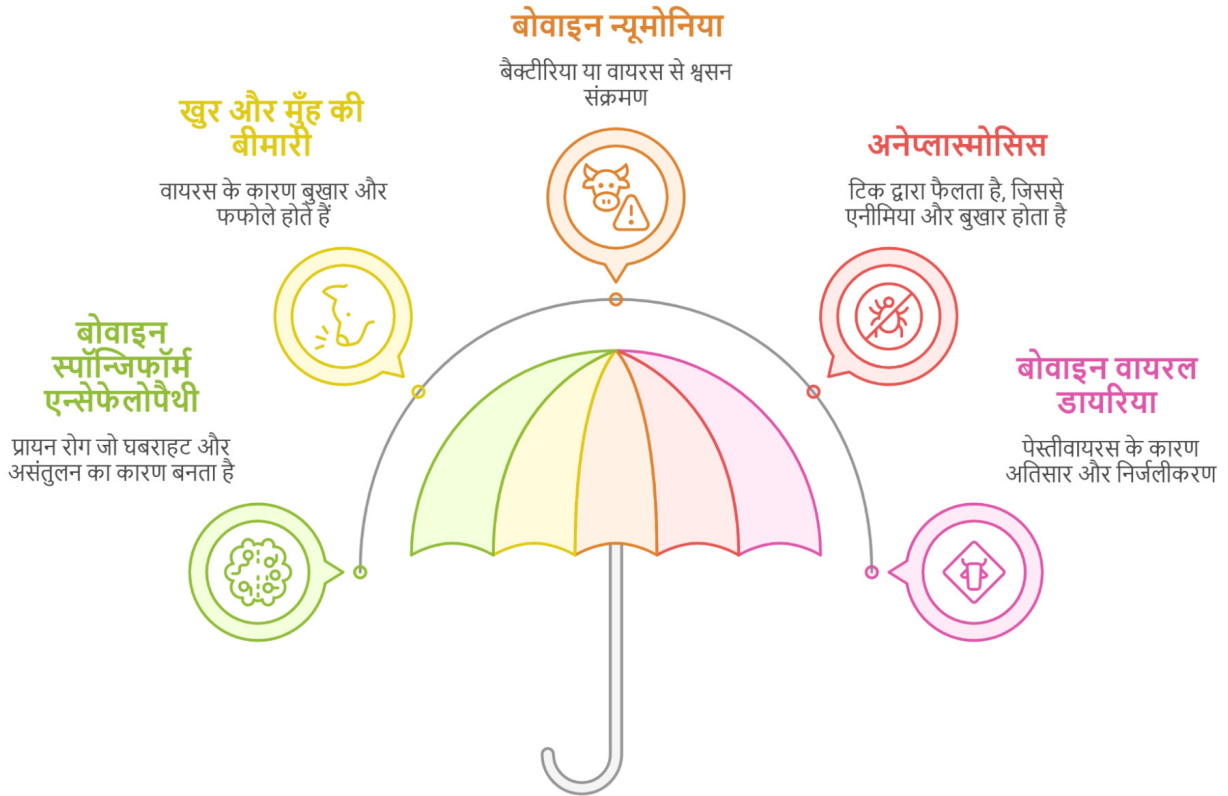


दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ वर्ल्ड असेंबली ऑफ डेलीगेट्स, WOAH का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें भारत सहित सभी 183 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- 🕒 प्रतिवर्ष इसकी बैठक पेरिस में होती है, जिसमें प्रत्येक देश को एक मताधिकार प्राप्त होता है।

मवेशियों में सामान्य रोग



मध्य प्रदेश में ब्लैकबक का अवैध शिकार

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में शिकारियों के एक समूह द्वारा जानवरों के एक झुंड पर गोली चलाने के बाद एक **कृष्णमृग** (ब्लैकबक) की मृत्यु हो गई।

- ❖ वन विभाग ने **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत मामला दर्ज किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2008 से 2018 के बीच 13 राज्यों में 139 लुप्तप्राय काले हिरण मारे गए।

- इन हत्याओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई, उसके बाद कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है।

मुख्य बिंदु

- ब्लैकबक के बारे में:
- ब्लैकबक (*Antelope cervicapra*) कृष्णमृग या भारतीय मृग, भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग प्रजाति है।
 - ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में (संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में) व्यापक रूप से पाए जाते हैं।
 - इसे **घास के मैदान** का प्रतीक माना जाता है।
 - इसे **चीते** के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना जाता है।
 - यह एक दैनंदिनी मृग (*Diurnal Antelope*) है अर्थात् यह मुख्य रूप से दिन के समय ज़्यादातर सक्रिय रहता है।
 - यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है।
- सांस्कृतिक महत्व:
 - यह हिंदू धर्म के लिये पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि इसकी त्वचा और सींग को पवित्र अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिये यह सौभाग्य (**Good Luck**) का प्रतीक है।
- संरक्षण स्थिति:
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
 - आईयूसीएन (IUCN) में स्थान: कम चिंतनीय (Least Concern)
 - CITES: परिशिष्ट-III
- खतरे:
 - इनके संभावित खतरों में प्राकृतिक आवास का विखंडन, वनों का उन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएँ, अवैध शिकार आदि शामिल हैं।
- संबंधित संरक्षित क्षेत्र:
 - वेलावदर कृष्णमृग अभयारण्य : गुजरात
 - पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभयारण्य : तमिलनाडु
 - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान : मध्य प्रदेश
 - ताल छापर अभयारण्य : राजस्थान
 - वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के समीप यमुना-पार क्षेत्र (Trans-Yamuna Belt) में कृष्णमृग **संरक्षण रिज़र्व** स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी। यह कृष्णमृग को समर्पित पहला संरक्षण रिज़र्व होगा।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम,**
1976: वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद**
48 A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद**
51 A (g): वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⌚ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⌚ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⌚ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⌚ IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⌚ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⌚ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⌚ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⌚ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⌚ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⌚ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⌚ रामसर कन्वेंशन
- ⌚ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⌚ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⌚ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⌚ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



तानसेन का मकबरा

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्वालियर स्थित हज़रत शेख मोहम्मद ग़ौस की मज़ार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया तथा स्मारक के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

❖ सम्राट अकबर के दरबार के महान संगीतकार तानसेन की कब्र इसी स्मारक परिसर में स्थित है।

मुख्य बिंदु

❖ उच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि तानसेन तथा हज़रत शेख मोहम्मद ग़ौस (एक श्रद्धेय सूफी संत) का मकबरा, प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व का संरक्षित स्मारक है।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) तथा ज़िला प्रशासन इस स्थल की अखंडता बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

❖ मकबरे के बारे में:

- इस मकबरे का निर्माण सूफी संत शेख मोहम्मद ग़ौस की मृत्यु के बाद किया गया था तथा यह सम्राट अकबर के शासनकाल (1556–1605) के सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है।
- इस मकबरे में कई ऐसी विशेषताएँ समाहित हैं, जो बाद की मुगल वास्तुकला, विशेषकर पूर्वी भारत में, सामान्य रूप से अपनाई गई।
 - ❑ इसका ढाँचा वर्गाकार है, जिसमें एक बड़ा और चपटा गुंबद तथा दोनों ओर छतरियाँ हैं, जो इसे बहुस्तरीय रूप प्रदान करती हैं।
 - ❑ केंद्रीय कक्ष के चारों ओर एक बरामदा है, जो बारीक नक्काशीदार पत्थर की जालियों से सुसज्जित है, जो गुजरात की स्थापत्य शैली से प्रभावित है।
- इस मकबरे की रूपरेखा ने बाद की मुगलकालीन संरचनाओं को भी प्रभावित किया, जिनमें फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी शामिल है।



❖ तानसेन के बारे में:

- तानसेन का जन्म लगभग 1500 ई. में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में वे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए।
- सूफी परंपरा के अनुसार, तानसेन शेख मोहम्मद ग़ौस के शिष्य थे।
- उन्हें उनकी ध्रुपद रचनाओं और रागों पर अद्वितीय अधिकार के लिये ख्याति प्राप्त हुई, जो ऐसे संगीतात्मक ढाँचे होते हैं जिन्हें विशिष्ट भावनाओं या प्रकृति के तत्त्वों को उद्बोधित करने हेतु रचा गया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ किंवदंतियों के अनुसार, उनकी गायन-शैली में चमत्कारी प्रभाव था, जैसे जंगली जानवरों को शांत करना, पक्षियों और शेरों जैसी ध्वनियों की नकल करना, यहाँ तक कि दिन के समय को बदल देना।
- ❖ तानसेन ने **मुगल सम्राट अकबर** के दरबार में स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने **कलात्मक प्रतिभा** को अत्यंत महत्व दिया और उस युग के कई प्रख्यात विद्वानों तथा कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया।
- ❖ वे अकबर के दरबार के **नवरत्नों** अर्थात् “नौ रत्नों” में से एक थे।
- ❖ उनकी **असाधारण संगीत प्रतिभा** की सराहना करते हुए, अकबर ने उन्हें “मियाँ” की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है— “गुरु” या “श्रेष्ठ पुरुष”।
- ❖ **तानसेन** की मृत्यु वर्ष **1586** या **1589** के आसपास हुई तथा उन्हें **ग्वालियर** में दफनाया गया।

पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958

- ❖ इस अधिनियम का उद्देश्य आगामी पीढ़ियों के लिये प्राचीन संस्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करना है।
- ❖ यह अधिनियम **सार्वजनिक अथवा निजी स्वामित्व वाली 100 वर्ष से अधिक पुराने संस्मारकों** पर लागू होता है।
- ❖ इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की मंजूरी के बिना **प्राचीन स्मारकों के समीप निर्माण अथवा कोई परिवर्तन करना प्रतिबंधित है।**
- ❖ **AMASR अधिनियम के तहत स्थापित NMA** संस्मारकों और स्थलों (केंद्रीय रूप से नामित संस्मारकों के समीप प्रतिबंधित/प्रतिबंधित क्षेत्रों) के रखरखाव तथा संरक्षण के लिये जिम्मेदार है।
- ❖ NMA, AMASR अधिनियम को कार्यान्वित करने और संरक्षित तथा विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण अथवा विकासात्मक गतिविधि के लिये अनुमति देने के लिये जिम्मेदार है।
- ❖ **संरक्षित क्षेत्र स्मारक के चारों ओर 100 मीटर की परिधि है,** जिसके बाहर 200 मीटर तक एक विनियमित क्षेत्र है।
- ❖ वर्तमान प्रतिबंध संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर की **परिधि** में निर्माण पर रोक लगाते हैं और साथ ही अतिरिक्त 200 मीटर के दायरे में परमिट हेतु कठोर नियम हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूप
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

